>

Title: Need to expedite the construction of Mahi Bajaj Sagar Project in Banswara, Rajasthan.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): माही नदी का पानी जालौर सिरोही जिले को सुलभ कराने की महत्वाकांक्षी योजना 25 साल से कागजों में दफन है। ऐसे में आमजन की उम्मीदें भी टूटने लगी है। दरअसल वर्ष 1966 में राजस्थान व गुजरात सरकार में हुए समझौते के अनुरूप माही परियोजना की कवायद शुरू हुई। इस के बाद गुजरात सरकार ने राज्य को पानी की आवश्यकता का हवाला देते हुए पानी देने से मना कर दिया। बाद में समझौता कमेटी के जरिए इस पर सहमति बनाने के प्रयास किए गए। वर्ष 1988 में आखिर बार इस पर मंथन किया गया। इसके बाद से यह परियोजना कागजों में दफन है। परियोजना के तहत बांसवाड़ा से सुंग बनाकर जालौर सिरोही व बाड़मेर के अनेक गांवों को माही नदी से पानी दिया जाना था। परियोजना को माही क्रॉसिंग पर अनास पिकवियर व चैनल के जरिए डूंगरपुर जिले के टिमरूआ गांव के पास माही नदी से शुरू कर जालौर के बागोड़ा उपखंड अंतर्गत बिशाला गांव तक प्रस्तावित किया गया था। योजना से समांतर 5.94 लाख एवं 7.11 लाख एकड़ भूमि को लिफ्ट से सिंचित किया जाना प्रस्तावित था। माही बजाज परियोजना की खोसला कमेटी एवं राजस्थान-गुजरात समझौते के अनुसार पानी की मात्रा 40 टीएमसी है। निष्पादित अनुबंध के अनुसार गुजरात राज्य से राजस्थान में उपयोग के लिए सहमति प्राप्त करने एवं इस जल उपयोग के माही बेसिन मास्टर प्लान का कार्य राज्य सरकार स्तर पर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी नई दिल्ली को आवंटित किया हुआ है। जालौर जिला में कम वर्षा के चलते एवं गिरते भू-जल स्तर से पूरा जिला डार्क जोन घोषित किया जा चुका है। गिरते भू-जल स्तर के स्थाई समाधान व जिले को हरा-भरा बनाने के लिए माही बांध की वर्षों पुरानी प्रस्तावित योजना को मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। अतः पिछले 25 वर्षों से कागजों में दम तोड़ रही माही बजाज परियोजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाए।